केन्द्रीय सरकार उस समय सामने आती है जब राज्यों के संसाधन उनकी आवश्यकताओं की अपेक्षा कम हो जाते हैं तथा उन्हें योजना के लिए अग्रिम सहायता की आवश्यकता होती है। चूंकि सहायता केवल प्लान योजना के लिए निर्मुक्त की जाती है अतः केन्द्र में ऐसी सहायता के उपयोग की जांच करने के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं है।

**बिहार के लिये जर्सी नस्ल की गाय**

1111. **श्री धुवराव** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य को मार्च, 1977 में भारत सरकार के माध्यम से आस्ट्रेलिया से उच्चतर स्वस्थ जर्सी नस्ल की 101 गायें प्राप्त हुई;

(ख) क्या उनके लाने में 50 लाख रु० खर्च हुए;

(ग) क्या ये सभी गायें गर्भवती थीं जिनमें से 39 मर गई तथा अन्य गायों को गर्भपात हो गया; और

(घ) यदि हां, तो इस पूरी न हो सकने वाली क्षति के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला)** : (क) बिहार को 99 जर्सी बछड़ियां और 2 जर्सी सांड (कुल 101 पशु) प्राप्त हुए हैं।

(ख) जी नहीं। उनके खाने-लेजाने पर लगभग 5 लाख रु० का खर्च हुआ है।

(ग) अधिकांश गायें गर्भावस्था की प्राथमिक स्थिति में थीं। 38 गाय और एक सांड, कुल 39 पशुओं की मृत्यु हुई और 39 अन्य गायों का गर्भपात हो गया। 14 गाय अभी भी गाभिन हैं।

(घ) बिहार सरकार ने इस बात की पूर्णतः जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की है और ऐसी दुर्घटना भविष्य में न हो, इसके लिए समुचित कार्यवाही की जाएगी।

**Central aid for Housing Projects in Gujarat State**

1112. SHRI PRASANNBHAI MEHTA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether Union Government have been asked by the State Government of Gujarat to give more aid for the development of land in the State to be made fit for the housing projects for the poor;

(b) if so, how much aid was given by the Centre to the State Government for the last three years for this purpose; and

(c) how much aid will be given to the State Government during the current financial year?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Apart from the allocation of L.I.C. loan to the State Governments including the Government of Gujarat, which is expected to be setlted shortly, it is difficult to indicate any other aid which the Central Government can give, as it would depend very much on the type of projects which the State Governments would formulate and present.